संख्या-60/2015/731/78-2-2015-38आई.टी./2015

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
समाज कल्याण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/माध्यमिक शिक्षा/अल्प संख्यक कल्याण /पशुपालन/राजस्व/कृषि/नगर विकास/ग्राम्य विकास/ विकलांग कल्याण/श्रम/ ऊर्जा/सचिवालय मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इलेक्टानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 11 जून, 2015**

विषयः मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु मेगा कॉल सेन्टर परियोजनान्तर्गत नोडल अधिकारी के नामांकन कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु एक 300 सीटर मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना एवं संचालन के लिए उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लि0 (यूपीडेस्को) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। सेन्टर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चलायी जा रही प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी देना तथा लाभार्थियों से पूर्व निर्धारित प्रश्नावली पर स्वतन्त्र फीडबैक प्राप्त कर योजनाओं के उचित संचालन की व्यवस्था करना है। इस प्रयोजनार्थ कन्सल्टेन्ट संस्था के सहयोग से यूपीडेस्को द्वारा सिस्टम इन्टीग्रेशन/कॉल सेन्टर आपरेटर के चयन हेतु आरएफपी तैयार कराया जा रहा है। परियोजना के सफल संचालन हेतु चयनित योजनाओं से सम्बन्धित विभागों में प्रत्येक से एक नोडल अधिकारी के नामांकन की आवश्यकता है ताकि यूपीडेस्को, कन्सल्टेंट संस्था मे0 अर्नेस्ट एण्ड यंग एलएलपी एवं चयनित होने वाले सिस्टम इन्टीग्रेटर/कॉल सेन्टर आपरेटर के प्रतिनिधियों द्वारा यथावश्यकता उनसे सम्पर्क कर योजनाओं का विवरण तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु अन्य तत्सम्बन्धी कार्यवाहियां पूर्ण करायी जा सकें।

2. यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि उत्तर प्रदेश के विकास हेतु वर्ष 2015-16 में रखे गए एजेण्डा सूत्र-146 से उक्त कार्य/योजना आच्छादित है और इसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने का उच्च स्तरीय निर्णय है। इसके अतिरिक्त उच्च स्तरीय निर्णयानुसार प्रथम चरण में इस परियोजनान्तर्गत उक्त विभागों/अधिष्ठानों की 17 योजनाओं (सूची संलग्न) का चयन किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग/अधिष्ठान से किसी एक सक्षम स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनके विवरण/दूरभाष नम्बर आदि उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0 (यूपीडेस्को) अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ को उच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि यूपीडेस्को एवं कन्सल्टेंट संस्था को विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाओं, मेगा कॉल सेन्टर के संचालन में प्रारम्भिक स्तर पर कॉल सेंटर एक्जक्यूटिव्स/रिसोर्सेज को सम्बन्धित योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण एवं प्रश्नावली निर्धारण/अनुमोदन आदि के लिए सम्पर्क सूत्र/सिंगल प्वाइंट आफ कान्टैक्ट की व्यवस्था अतिशीघ्र उपलब्ध हो सके।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 60/2015/731(1)/78-2-2015 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी (श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा)।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/यूपीएलसी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभागवार योजनाओं की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	विभाग
1	समाजवादी पेंशन योजना	समाज कल्याण
2	लोहिया आवास योजना	ग्राम्य विकास
3	108 एवं 102 एम्बुलेंस सेवा	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
4	लैपटाप वितरण योजना	माध्यमिक शिक्षा
5	कन्या विद्याधन	माध्यमिक शिक्षा
6	पढ़े बेटियाँ और बढ़े बेटियाँ	माध्यमिक शिक्षा
7	हमारी बेटी उसका कल	अल्पसंख्यक कल्याण
8	कामधेनु योजना एवं मिनी कामधेनु कुक्कुट नीति	पशुपालन
9	कृषक दुर्घटना बीमा योजना	राजस्व
10	सोलन फोटो बोल्टेक एरीगेशन पम्प	कृषि
11	बैट्री पार्वड मोट्राइज्ड रिक्शा	नगर विकास
12	विकलांग पेंशन	विकलांग कल्याण
13	वृद्धावस्था पेंशन	समाज कल्याण
14	साईकिल वितरण	श्रम
15	राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण	ऊर्जा
16	नये उपकेन्द्रों की स्थापना	ऊर्जा
17	मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता	सचिवालय मुख्यमंत्री कार्यालय

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।